आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 11.03.2026
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- राज्य विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन में खेल, महिला सशक्तिकरण और राशन व्यवस्था पर चर्चा हुई।
- प्रदेश के आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति ने कहा– राज्य में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता। उपभोक्ताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 75 करोड़ 36 लाख रुपये की योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
- **और,** सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 12 वर्ष से अधिक समय से कोमा में रहे व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी।

विधानसभा सत्र

भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में खेल, महिला सशक्तिकरण और राशन वितरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिया। खेलों में पदक विजेता को रोजगार दिये जाने से जुड़े प्रश्न पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को ग्रेड और पदक के अनुसार नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए पद सृजन की कार्रवाई चल रही है। एक अन्य प्रश्न के जबाव में उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से प्रदेश के गरीब बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, प्रवर्तकता योजना और नन्दा गौरा योजना के तहत मानदेय और प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास से जुड़ी कई योजनाएं भी राज्य में संचालित हो रही हैं।

राशन वितरण के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य में एक लाख 84 हजार से अधिक राशन कार्डों का सत्यापन अभियान तेज किया गया है। अपात्र कार्ड निरस्त कर पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पिछले चार वर्षों में विभिन्न खाद्य योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल और एपीएल श्रेणी के आधार पर नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं।

खेल सुविधाओं को लेकर मंत्री ने बताया कि राज्य में 30 स्टेडियम और 102 मिनी स्टेडियम बनाए जा चुके हैं और प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।

बहस

बजट सत्र के तीसरे दिन के आज सदन में संसदीय परंपरा और कार्य संचालन को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस भी हुई। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विपक्ष सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में विपक्ष की पारंपरिक भागीदारी रही है, लेकिन अब एजेंडा बहुमत के आधार पर तय किया जा रहा है, जिससे गतिरोध की स्थिति बन रही है।

सदस्य मुन्ना सिंह चौहान ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सदस्य प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

धार्मिक पर्यटन

उत्तराखंड सरकार प्रदेश ने धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इस दिशा में हरिद्वार कुंभ, हरिद्वार–ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, नंदा देवी राजजात, सरयू रिवर फ्रंट सहित कई महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण को स्वीकृति । इससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है। उत्तराखंड दुनिया भर के सनातन मतावलंबियों की आस्था का केंद्र रहा है। प्रदेश सरकार, उत्तराखंड को धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन – तीर्थाटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। बद्रीनाथ – केदारनाथ पुनर्निर्माण के साथ ही मानसखंड मंदिर माला के तहत 48 मंदिरों के आस पास अवस्थापना विकास के कार्य प्रारंभ कर चुके है। इसके अलावा आगामी नंदा देवी राजजात के लिए 25 करोड़ रुपए के साथ ही स्प्रिचुअल इकोनॉमी जोन के लिए 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस बजट में सरकार ने संस्कृत पाठशालाओं के अनुदान के लिए भी 28 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार उत्तराखंड के धार्मिक स्वरूप को और अधिक निखारने की दिशा में कार्य कर रही है और कई अन्य स्थलों को भी विकास के लिए तलाशा जा रहा है।

एलपीजी आपूर्ति

मध्य पूर्व एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए उत्तराखंड में गैस आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में खाद्य विभाग और तेल कंपनियों के साथ राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में घरेलू गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

वहीं पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाती एस भदौरिया ने कहा कि, जिले में अभी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान अनावश्यक भण्डारण न करे। इसके लिए निगरानी की जा रही है।

वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 75 करोड़ 36 लाख रुपये की योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। देहरादून जिले की विधानसभा क्षेत्र मसूरी के तहत न्यू कैंट मोटर को दो लेन में अपग्रेड करने के लिए सोलह करोड़ 87 लाख की धनराशि, विधानसभा क्षेत्र चंपावत के तहत टनकपुर शारदा नदी और उचौलीगोठ में बाढ़ सुरक्षा के लिए 15 करोड़ 69 लाख की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र पौड़ी ब्लाक विकासखण्ड पाबौ मे बेडा का जगड मोटर मार्ग, राजकीय उपजिला चिकित्सालय रुड़की में विद्युत रिवाईरिंग कार्य, नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्र में एकत्रित पुराने जमा कचरा निस्तारण पिथौरागढ़ में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण समेत अन्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

महिला दिवस

प्रदेश भर में राज्य महिला आयोग 9 से 13 मार्च तक 'महिला आयोग, आपके द्वार' अभियान के तहत जन सुनवाई आयोजित कर रहा है। जनसुनवाई का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना और उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करना है। हरिद्वार जिले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बताया कि सभी जिलों में जन सुनवाई चल रही है और इस दौरान घरेलू हिंसा समेत अन्य मामलों का निस्तारण किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 32 वर्षीय एक व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी है। न्यायालय ने पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा में पडे व्यक्ति के कृत्रिम जीवन रक्षक यंत्र को हटाने की अनुमति दे दी है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जीवन रक्षक यंत्र या उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक उपचार को रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है। गाजियाबाद के रहने वाले पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र हरीश राणा को 2013 में अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोटें आईं थी। इसके बाद से वह एक दशक से अधिक समय से कोमा में हैं।

हिमालयन कल्चरल कॉर्निवाल

पिथौरागढ़ जिले में प्रथम हिमालयन कल्चरल कॉर्निवाल अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। कॉर्निवल का उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध लोक विरासत और संस्कृति को सहेजना है। आज जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन की रूपरेखा तय की गई। कॉर्निवाल में हिमालयी राज्यों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि हिमालयी क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं व लोक कलाओं का व्यापक प्रदर्शन किया जा सके। आयोजन को लेकर विभिन्न समितियों का भी गठन कर लिया गया है।

चारधाम यात्रा

चारधाम यात्रा के दृष्टिगत रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर स्थित समस्त व्यवसायिक आवासीय इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि समस्त होटल, लॉज, रिजोर्ट, धर्मशाला व होमस्टे समस्त व्यवसायियों को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया कि नियम विरुद्ध संचालन करने पर दस हजार रुपए तक अर्थदंड वसूला जाएगा।